

हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कराने के लिए स्पीकर के ओएसडी सुप्रीम कोर्ट जायेंगे?

दूसरी ओर, एफआईआर दर्ज कराने के लिए याचिका दर्ज कराने वाले प्रार्थी शेखर मेवाड़ा व कैलाश राम ने सुप्रीम कोर्ट में “केविएट” फाइल की, 5 अगस्त को इस मामले में

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 6, अगस्ता। एक अहम घटनाक्रम में, अब तक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के ओएसडी राजीव दत्ता के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जबकि राजस्थान हाईकोर्ट और न्यायाधीश समीर जैन ने 4 अगस्त को ही एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया था।

इससे भी ज्यादा चौंकाने और स्तब्ध कर देने वाली बात यह है कि राजस्थान के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव शर्मा को ओम बिड़ला ने दिल्ली बुलाया था, जहां उन्होंने बिड़ला और राजीव दत्ता, दोनों से मुलाकात की।

संभवतः यह पहला अवसर है, जब किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उस आरोपी से मुलाकात की है, जिसके

- जैसा कि विदित ही है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश समीर जैन ने, लोकसभाध्यक्ष ओम बिड़ला के ओएसडी राजीव दत्ता के खिलाफ ‘ह्यूमन ट्रेफिकिंग’ के मामले में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश चार अगस्त को पारित किये थे।
- अजीबोगरीब बात यह भी है कि कांग्रेस ने भी किन्हीं कारणों से इस प्रकरण में चुप्पी साधने का निर्णय सा ले लिया है। क्योंकि, जब किसी कनिष्ठ कर्मचारी ने इस मामले की खबर, पीसीसी की वैबसाइट पर डाली तो तुरन्त आदेश आ गया, पार्टी के उच्चतम स्तर से, कि प्रकरण की स्टोरी वैबसाइट पर नहीं दिखाई जाए।

खिलाफ राज्य के हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया हो।

हालांकि मुलाकात के दौरान क्या बातचीत हुई, यह केवल कयास ही है, लेकिन पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों में इस बात को लेकर

खासी चर्चा और उत्सुकता है कि लोकसभा अध्यक्ष ने डीजीपी को क्या निर्देश दिए होंगे।

सूत्रों के अनुसार, कथित रूप से मानव तस्करी के आरोपों का सामना कर रहे राजीव दत्ता अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि

हाईकोर्ट के एफआईआर दर्ज करने और जांच करने के आदेश को रद्द कराया जा सके। इसके लिए वे एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल कर रहे हैं।

याचिकाकर्ताओं, शेखर मेवाड़ा और कैलाश राम ने, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए तथा गड़बड़ी की आशंका के कारण पहले ही, 5 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है, ताकि बिना उनका पक्ष सुने कोई फैसला न हो सके।

राजस्थान और दिल्ली की सत्ता के गलियारों में दत्ता के इस मामले को लेकर काफी चर्चा और दिलचस्पी देखी-सुनी जा रही है।

दिलचस्प बात यह है कि किसी भी कांग्रेस नेता ने अब तक इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया

नयी दिल्ली, 06 अगस्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत यहां बने केन्द्रीय सचिवालय भवनों में से एक कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर उनके साथ केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल भी थे। इस दौरान मोदी ने कर्तव्य भवन का दौरा किया और यहां बनायी गयी सभी सुविधाओं का निरीक्षण

- 50 हजार वर्ग मीटर में फैला यह भवन पूर्णतया ईकोफ्रेंडली है, और कई प्रमुख मंत्रालयों के कार्यालय इसी भवन में बनाए जाएंगे।

भी किया।

यह लगभग एक लाख 50 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला एक अत्याधुनिक कार्यालय परिसर है, जिसमें दो बेसमेंट और सात तल (भूतल 6 तल) हैं। इसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय विभाग और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महेश जोशी की जमानत याचिका पर ईडी की बहस पूरी

जयपुर, 6 अगस्ता। राजस्थान हाईकोर्ट में जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े ईडी प्रकरण में आरोपी पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका पर ईडी की बहस पूरी हो गई है। अदालत ने मामले में प्रति-जवाब पेश करने के लिए याचिकाकर्ता को 8 अगस्त का समय दिया है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने ये आदेश महेश जोशी की जमानत याचिका पर

- याचिकाकर्ता 8 अगस्त को प्रति जवाब पेश करेंगे।

सुनवाई करते हुए दिए।

ईडी की ओर से याचिकाकर्ता की जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि प्रकरण में एसीबी की ओर से दर्ज अन्य एफआईआर में याचिकाकर्ता की भूमिका को बताया गया है। वहीं, याचिकाकर्ता के बेटे की फर्म में 50 लाख रुपए का लेनदेन किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से इस राशि की लौटाना भी बताया जा रहा है, तो राशि लौटाने से अपराध की गंभीरता कम नहीं होती है। याचिकाकर्ता और उसके बेटे ने विभाग की टेंडर प्रक्रिया में रिश्तव प्राप्त की है। इसके अलावा, धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 के तहत आरोपी को उस समय ही जमानत दी जा सकती है, जब अदालत इस बात से प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि वह इस अपराध का दोषी नहीं है। यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वह गवाहों को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप ने भारत पर रूस से “ऑयल” खरीदने के एवज़ में 25 प्रतिशत टैरिफ और लगाया

अमेरिका ने ऐसी पैनल्टी चीन पर लगाने की हिम्मत नहीं दिखाई, हालांकि, चीन भी भारी मात्रा में रूस से “ऑयल” खरीदता है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
वॉशिंगटन, 6, अगस्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत के निर्यात पर आज 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ (शुल्क) लागू कर दी है, जिसकी उन्होंने पहले ही धमकी दी थी। यह नया टैरिफ पहले से लगे 25 प्रतिशत के “पैसिप्रोकल टैरिफ” (प्रतिशोधी शुल्क) के ऊपर जोड़ा जाएगा, जिससे कुल शुल्क अगले 21 दिनों में 50 प्रतिशत हो जाएगा।

इस नए कदम के साथ ही, ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर पहला “सेकन्डरी सैंक्शन” लगा दिया है, जबकि रूस के तेल के दूसरे बड़े खरीदार चीन पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

इस संयुक्त शुल्क से भारत एक विशेष स्थिति में आ जाएगा, जिसमें उस पर अमेरिका का सबसे ऊंचा 50 प्रतिशत शुल्क लगेगा। इसका सीधा असर यह हो सकता है कि भारतीय निर्यात पूरी तरह से अमेरिकी बाजार से बाहर हो जाए, क्योंकि कीमतें बहुत

- इस बड़े हुए टैरिफ के कारण भारतीय माल अमेरिका के बाजारों से लुप्त ही हो जाएगा तथा भारत को अन्य मार्केट ढूंढ़ने पड़ेंगे, अपना माल बेचने के लिए।
- पर, रूस के अलावा अन्य स्रोतों से ऑयल खरीदने का विकल्प नहीं बचा है भारत के समक्ष। क्योंकि, अन्य स्रोतों से ऑयल की खरीद बहुत महँगी पड़ेगी भारत को।
- भारत का अमेरिका को निर्यात बहुत कम है तथा निर्यात बंद होने से इतना नुकसान नहीं होगा, जितना “ओपन मार्केट” से ऑयल खरीदने से होगा।
- चीन पर पैनल्टी नहीं लगाने से ट्रंप की “टी.ए.सी.ओ.” (ट्रंप आलवेज़ चिकन्स आउट) की छवि को और स्पष्ट और मजबूत कर देता है।

बढ़ जाएंगी।

ट्रंप ने यह घोषणा ऐसे समय में की है, जब अमेरिका की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत चल रही है। ट्रंप रूस पर दबाव बनाना चाहते हैं कि वे जल्दी से यूक्रेन में अपना युद्ध समाप्त करें।

चाहे अनचाहे, इस कदम ने भारत

को अमेरिका और रूस जैसी प्रतिद्वंद्वी महाशक्तियों के बीच चल रही भू-राजनीतिक खींचतान के बीच में लाकर खड़ा कर दिया है, जो यूक्रेन युद्ध को लेकर एक-दूसरे के खिलाफ रणनीतिक दांव-पेंच खेल रहे हैं। भारत ने ट्रंप की भारतीय निर्यात पर सेकन्डरी प्रतिबंध

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विपक्ष ने संसदीय गतिरोध खत्म करने का समाधान दिया सरकार को

विपक्षी दलों ने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के बजाय चुनाव सुधार पर चर्चा करवाने की पेशकश की

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 6 अगस्ता। एक रचनात्मक पहल करते हुए, विपक्ष ने कथित रूप से पीठासीन अधिकारी और सत्तापक्ष को “मध्य मार्ग” के रूप में एक सुझाव दिया है कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इन्टेन्सिव सिविज्गन/एस.आई.आर.) पर बहस की मांग को लेकर संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए “चुनावी सुधारों” पर चर्चा कराई जाए।

हालाँकि, सरकार ने इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन विपक्षी दलों के सूत्रों का कहना है कि सरकार इस तरह की किसी भी बहस को अनुमति देने के मूड में नहीं है।

बुधवार को लोकसभा में

- लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने एक्स पर पोस्ट में बताया कि संसद में किन-किन वर्षों में चुनाव सुधार पर चर्चा हुई है।
- केन्द्र सरकार ने विपक्ष के प्रस्ताव पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। विपक्षी दलों के सूत्रों ने कहा कि ऐसा लगता है, सरकार चुनाव सुधार पर चर्चा कराने की इच्छुक भी नहीं है।

एस.आई.आर. पर चर्चा की मांग के दौरान केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि लोकसभा के नियम विचाराधीन (सब- जूडिस) मामलों पर चर्चा की अनुमति नहीं देते। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग जैसी स्वायत्त संस्थाओं के कामकाज पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती।

इस बीच, कांग्रेस महासचिव

(संचार) जयराम रमेश ने लोकसभा में पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई की एक पोस्ट का हवाला दिया, जिसमें दावा किया गया कि संसद में चुनावी सुधारों और चुनाव आयोग के कामकाज पर चर्चा का एक लंबा इतिहास रहा है।

रमेश ने कहा कि गोगोई ने गहन शोध किया है और “मोदी सरकार के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कैलाश मानसरोवर यात्रा रोकी गई

नैनीताल, 06 अगस्ता। उत्तराखंड के कुमाऊं में बादल फटने का कहर फिलहाल बुधवार शाम को थम गया, लेकिन उसका असर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर पड़ा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा बुधवार को धारचूला से आगे नहीं बढ़ पाई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कैलाश मानसरोवर यात्रा का 48 सदस्यीय चौथा दल मंगलवार को

- उत्तराखंड में आई आपदा की वजह से यात्रा पर अस्थायी रोक लगाई गई है।

पिथौरागढ़ के धारचूला पहुंच गया था। रात्रि विश्राम के बाद, आज दल को उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित पहले आधार शिविर गुंजी पहुंचना था, लेकिन अतिवृष्टि के चलते भूस्खलन होने से धारचूला-लिपुलेख मार्ग कई जगह अवरुद्ध हो गया।

एस.सी.ओ. सम्मेलन में प्र.मंत्री मोदी जायेंगे इस माह भारत की कूटनीति के लिए यह परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि भारत ऐसी स्थिति में नहीं पड़ना चाहता, कि दोनों “सुपर पावर” ग्रुप में से एक-एक का चयन करना पड़े उसे

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 6 अगस्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने के अंत में चीन जा रहे हैं, जहाँ वे शंघाई कोऑपेरेशन आर्गनाइजेशन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ रहा है और भारत प्रमुख शक्तियों की आपसी प्रतिद्वंद्विता के बीच फंसा हुआ है। इस यात्रा की पृष्ठभूमि विशेष रूप से जटिल है, अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने संरक्षणवादी आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाते हुए भारत पर रूस से तेल आयात कम करने का दबाव भी बना रहे हैं, जबकि रूस, भारत का लंबे समय से रणनीतिक

साझेदार रहा है। इन घटनाओं ने भारत की कूटनीतिक गुंजाइश को सीमित कर दिया है, जिससे नई दिल्ली के लिए अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं में विविधता लाना आवश्यक हो गया है। इस पृष्ठभूमि में, मोदी की चीन पहल को एक रणनीतिक पुनर्संतुलन के रूप में देखा जा रहा है, एक ऐसा कूटनीतिक दांव, जो अमेरिकी दबाव को कम करने में सहायक हो सकता है। भारत भले ही वॉशिंगटन के साथ अपने संबंधों के प्रति प्रतिबद्ध हो, विशेषकर प्रौद्योगिकी, रक्षा और ईंडो-पैसिफिक सुरक्षा ढांचे में, लेकिन बीजिंग के साथ नए सिरे से संवाद एक अधिक संतुलित विदेश नीति का संकेत देता है, जो रणनीतिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देती है। यह स्पष्ट संदेश है कि भारत

- भारत, अमेरिका के साथ टैक्नॉलजी, डिफेंस सहयोग तो चाहता है, पर, क्षेत्रीय मामलों में अपने हितों के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता की इच्छा भी रखता है।
- साथ ही पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा किये गये नरसंहार वाकिया भी ताज़ा है, भारत के दिलो-दिमाग पर। अतः, चीन द्वारा पाकिस्तान का पक्ष लेना हर मामले में, चाहे वह मामला आतंकवादी गतिविधियों के बारे में ही क्यों न हो, भारत के लिए पीड़ादायक अहसास है।
- एस.सी.ओ. सम्मेलन में वॉशिंगटन, मॉस्को व बीजिंग के बीच कैसे संतुलन बैठाकर आगे बढ़ा जाए, यह भारत के लिए वाकई में चुनौती है।
- चर्चा है कि सम्मेलन के दौरान प्र.मंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन व चीन के प्रेंसिडेंट शी जिनपिंग से भी मुलाकात कर सकते हैं।

प्रतिद्वंद्वी वैश्विक शक्तियों के बीच किसी एक पक्ष का चयन करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

हालांकि, यह संवाद कई

जटिलताओं से भरा हुआ है। यह यात्रा उस समय हो रही है, जब कश्मीर के पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले में कई भारतीय सुरक्षा कर्मियों और

नागरिकों की जान चली गई। इस घटना ने पाकिस्तान के प्रति चीन के रुख को लेकर भारत की चिंताओं को फिर से उभार दिया है, विशेष रूप से इस बात

को लेकर कि चीन अब भी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने से हिचकता है। बीजिंग का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे वैश्विक मंचों पर बार-बार पाकिस्तान का बचाव करना, भारत और चीन के बीच तनाव का प्रमुख कारण रहा है।

ऐसे में, चीन के शीष नेतृत्व के साथ भारत की उच्चस्तरीय बैठकें केवल आर्थिक या सीमा-सम्बंधी कूटनीति तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि यह दोनों देशों के परस्पर विरोधी हितों के बीच संतुलन साधने की एक चुनौतीपूर्ण कवायद होगी। क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं को आर्थिक साझेदारी और एशिया में रणनीतिक प्रभाव बनाए रखने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एक अक्टूबर से बहाल होंगी एयर इंडिया की अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें

नई दिल्ली, 06 अगस्ता। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद एयर इंडिया के विमानों का परिचालन बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, हालांकि अब

- अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद सुरक्षा जांच लंबित होने की वजह से एयर इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय सेवा पर आंशिक रोक लगा दी गई थी।

धोरे-धोरे एयर इंडिया के विमानों की आवाजाही सामान्य होती जा रही है। इस बीच बुधवार को एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया के सीईओ कैप्टेन विल्सन ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)